भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †601

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

जनजातीय आबादी की प्रगति और कल्याण

†601. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रौद्योगिकी, पिछड़ापन और सामाजिक आर्थिक बाधाएँ जनजातीय लोगों की प्रगति और कल्याण को अवरुद्ध कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): देश भर में 75 पीवीटीजी सहित 705 से अधिक जनजातीय समुदाय फैले हुए हैं जो ऐतिहासिक रूप से जंगलों, पहाड़ियों, पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां पहुंचना कठिन है और जहां भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के संबंध में चुनौतियां हैं। स्वतंत्रता के बाद, जनजातीय विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और मॉडल विकसित किए गए हैं। जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) 1974-75 में अस्तित्व में आई और तब से इसमें कई बदलाव हुए हैं (जिसे बाद में अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना गया)। हालाँकि, मूल विचार (दर्शन) वही रहा है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाकर एक साथ काम करने की आवश्यकता है । पिछले 10 वर्षों में, अजजा के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत बजट आवंटन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 24,598 करोड़ रु. (2013-14 में) से 2023-24 के दौरान 1,19,509 करोड़ रुपये तक 5 गुना बढ़ गया है। अजजा के लिए विकास योजनाओं हेतु 42 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को डीएपीएसटी के तहत बजट अनुदान आवंटित किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के लिए सड़क, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए मानदंडों में ढील (शिथिलता) दी गई

है। मंत्रालय ने क्षेत्रीय मंत्रालयों द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (stcmis.gov.in) विकसित किया है। डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2019 और 2022 में अंत्योदय मिशन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य डीएपीएसटी निधियों के साथ अभिसरण से जनजातीय गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को 24,104 करोड़ रुपये के बजट के साथ 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र के जंगलों और दूरदराज के इलाकों में स्थित लगभग 30,0000 बस्तियों में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों (11 लाख परिवारों) के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत, सभी संबंधित योजनाओं के लिए जनसंख्या मानदंडों में ढील (शिथिलता) दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण और आंगनवाड़ी स्थापित करने के लिए मानदंडों में ढील (शिथिलता) देकर 100 कर दिया गया। जलजीवन मिशन के लिए 20 परिवारों वाली बस्तियों के लिए सामुदायिक नल उपलब्ध कराने के लिए जन जीवन मिशन के मानदंडों में ढील (शिथिलता) दी गई है। शेष गैर-विद्युतीकृत घरों तक बिजली की पहुंच के प्रावधान के लिए नवस्वरुपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) (विद्युत मंत्रालय) के मानदंडों में ढील (शिथिलता) दी गई है। जिन परिवारों के लिए ग्रिड के माध्यम से बिजली संभव नहीं है, उनके लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से घरों को ऊर्जा प्रदान करने के मानदंडों में पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए नई सौर ऊर्जा योजना के माध्यम से ढील (शिथिलता) दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए, मिशन में पीवीटीजी छात्रावासों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और बहुउद्देशीय केंद्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें 9 मंत्रालयों द्वारा 11 उपाय (हस्तक्षेप) किए गए हैं।

मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू करता है, जिसके तहत हर साल 35 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2500 करोड़ रुपये से अधिक है। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजनाओं के राज्य पोर्टल को डीबीटी जनजातीय पोर्टल के साथ एकीकृत करके छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में छात्रवृत्ति बजट 2.5 गुना बढ़कर 2013-14 में 978 करोड़ से 2023-24 में 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने 2019 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है, जिसके तहत 50% या उससे अधिक अजजा आबादी और 20,000 या उससे अधिक जनजातीय लोगों वाले हर ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा, जो नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होगा। दूरदराज के जनजातीय इलाकों में 440 नए स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। 2018 तक अनुच्छेद 275(1) के तहत पहले से ही 288 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है, 2026 तक कुल 728 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 452 नए स्कूलों के लिए ईएमआरएस की निर्माण लागत 2021-22 में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 48 करोड़ रुपये कर दी गई है। पुराने स्कूलों को 5 करोड़ रुपये प्रति स्कूल की

दर से अपग्रेड करने और 5 करोड़ रुपये प्रत्येक खेल उत्कृष्टता केन्द्र की दर से 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत 28919.72 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। चरणबद्ध तरीके से 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिनमें से 10,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का लक्ष्य राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीद करने में सहायता करने के अलावा वन धन विकास केंद्र/वन धन उत्पादक उद्यम स्थापित करके फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करके देश भर में आजीविका संचालित जनजातीय विकास प्राप्त करने का प्रयास है। इस योजना के तहत हाट बाजार, गोदाम स्थापित करने का भी प्रावधान है। पीएमजेवीएम योजना के तहत पांच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए ट्राइफेड कार्यान्वयन एजेंसी है। वन धन कार्यक्रम जिसे 2019 में शुरू किया गया था, के तहत **28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों** में **10 लाख** से अधिक लोगों को कवर करने वाले 3800 से अधिक **धन विकास केंद्र (वीडीवीके)** स्वीकृत किए गए हैं। एमएफपी के लिए एमएसपी योजना के तहत कवर किए जाने वाले एमएफपी की अधिसूचित वस्तुओं की सूची में **87 एमएफपी** जोड़े गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिए सिकल सेल मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। रोग की रोकथाम, उपचार और उन्मूलन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया है। योजना की प्रगति, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए, मंत्रालय ने एक प्रदर्शन डैशबोर्ड (dashboard.tribal.gov.in) विकसित किया है, जिस पर जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों (हस्तक्षेपों) के विवरण देखे जा सकते हैं।

*****